प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' चउवन '

[25/2/2016]

प्रश्न सं. [क. 846]

परिशिष्ट

माननीय मुख्यमन्त्री जी द्वारा 02.मई 2008 में जिले में किये गये प्रवास के दौरान की गई घोषणाओं की जानकारी निम्नानुसार हैं :–

- गौरी तालाब के सम्पूर्ण जीर्णोद्धार हेतु 2 करोड रूपये दिये जाने ।
- कस्बा भिण्ड में सीवरलाइन डालने के लिए स्वीकृत किये जाने की घोषणा की गई।
- कनेरा सिंचाई उद्वहन परियोजना का कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा की गई ।
- ट्यूबवैल कनेक्शन पर 50 प्रतिशत की सबसिडी दिये जाने की घोषणा की गई ।

उक्त घोषणाओं के संबंध में संबंधित विभागों के द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई । जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

स0क्र0	घोषणा का विवरण	कार्यालय प्रमुख का नाम	की गई कार्यवाही
1	भिण्ड गौरी तालाब के संपूर्ण जीर्णोद्धार 2 करोड रू0 कलेक्टर के खाते में 29.07.2011 से जमा किये जाने बाबत । **घोषणा क0 4238**	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद भिण्ड	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद भिण्ड के पत्र क0 निर्माण 2015/393 दिनांक 11.02.2015 द्वारा सूचित किया गया है, कि उक्त कार्य हेतु पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) भोपाल द्वारा आदेश कमांक 1689 दिनांक 28.06.2011 से रूपये 50.00 लाख कलेक्टर भिण्ड + रूपये 2.50 लाख पीएफआरसी शुल्क @ 5 प्रतिशत के रूप में एप्को की स्वीकृति प्रदान कर विनुक्त की गई है । एप्को द्वारा प्रदत्त राशि कलेक्टर भिण्ड के खाते में दिनांक 29.07.2011 से जमा है । निकाय की मांग अनुरूप राशि प्रदाय की जावेगी ।
2	भिण्ड शहर की लंबित सीवर प्रोजेक्ट की स्वकृति दिये जाने । **घोषणा क्रमांक 4239**	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद भिण्ड	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद भिण्ड के पत्र क0 स्वा./2014/6199 दिनांक 22.11.2014 द्वारा अवगत कराया गया है, कि शहर में सीवर प्रोजेक्ट तैयार कराया जाकर निकाय द्वारा **UIDSSMT** योजना अन्तर्गत परिषद् के संकल्प कमांक 01 दिनांक 16.01.2014 को 289.33 करोड रूपये का प्रस्ताव तैयार कर पत्र कमांक 165 दिनांक 17.01.2014 से कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास ग्वालियर के अनुशंसा पत्र कमांक 41 दिनांक 20.01.2014 से मुख्य अभियंता नगरीय प्रशासन एव0 विकास भोपाल की ओर भेजी गई। जिसको मध्यप्रदेश शासन की ओर से केन्द्र सरकार की ओर मंजूरी हेतु भेजा गया, जो अभी प्राप्त नहीं हुई है ।
3 (अ)	कनेरा सिंचाई उद्दयन परियोजना का कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा की गई । **घोषणा क्रमांक 4240**	कार्यपालन यन्त्री जल संसाधन संभाग भिण्ड	योजना की स्वीकृति प्राप्त एवं बजट में शामिल है योजना अन्तर्गत मैकेनिकल कार्य के लिये एजेन्सी निर्धारित की जाकर कार्य प्रगति पर सिविल कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई है । कार्यालय कार्यपालन यन्त्री जल संसाधन भिण्ड के पत्र क0 2107 दिनांक 28.08.2010 के द्वारा जिला भिण्ड के अटेर विधान सभा क्षत्रे अन्तर्गत कनेरा ग्राम के पास चंबल नदी पर निर्माणाधीन कनेरा उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण हेतु निम्न कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है। 3. कनेरा उद्वहन सिंचाई योजना पर मैकनिक कार्यों की एजेन्सी निर्धारित कर पम्प एवं पाइप प्रदाय कर मार्च 2010 तक 1417.70 लाख व्यय किये जा चुके है । 4. सिविल कार्य एवं पक्के कार्यों की एजेंसी निर्धारित कर माह मार्च 20110 तक 431.75 लाख व्यय किया जा चुका है । चंबल घडियालक्षेत्र के बाहर कार्य प्रगति पर है
(ब)	ट्यूबवैल कनेक्शन पर 50 प्रतिशत की सबसिडी दिये जाने की घोषणा की गई ।	यन्त्री जल संसाधन संभाग भिण्ड	

	घोषणा क्रमांक 4240			घडियाल क्षेत्र में कार्य करने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन मान0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दिनां 16. 09.2009 को प्रस्तुत किया जा चुका है । कनेरा उद्‌वहन सिंचाई योजना का 414 हैक्टयर क्षेत्र में कार्य करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा जा चुका है । मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर द्वारा प्रस्ताव पर वन मण्डलाधिकारी मुरैना की अनुषंसा सहित प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क0 10349 दिनांक 07.10.2008 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी भोपाल को भेजा जा चुका है । तत्पश्चात वायोडायवर्सिटी प्रभाव के आकलन हेतु वाइल्ड लाइफ इन्स्टीटयूट देहरादून द्वारा ड्राफट रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है एवं अंतिम रिपोर्ट माह सितम्बर में प्रस्तुत किया जाना संभावित है तत्पष्चात रिपोर्ट म0प्र0 राज्य के वाइल्ड लाइफ बोर्ड को प्रेषित की जावेगी तत्पष्चात म0प्र0 राज्य वाइल्ड लाइफ बोर्ड की सहित प्रकरण साधिकार समिति नई दिल्ली को भेजा जाकर मान. सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त होते ही कार्य पूर्ण करने की कार्यवाही की जावेगी । वर्तमान में कार्यपालन यन्त्री जल संसाधन संभाग मुरैना के अधिन्यस्त है ।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग